गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ी

मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले, गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी में 21 फीसदी का इजाफा

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 8 अप्रैल

पश्चिम एशिया संकट के कारण उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ 2026 के लिए गैर-यूरिया उर्वरकों पर प्रति किलो सब्सिडी दरों में 10 से 21 फीसदी तक वृद्धि को मंजूरी दी है। यह वृद्धि खरीफ 2025 की तुलना में पोषक आधारित सब्सिडी स्कीम (एनबीएस) व्यवस्था के तहत की गई है। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 41,534 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, जो पिछले सीजन के बोझ से करीब 12 फीसदी ज्यादा है। इसका अर्थ है कि यदि यूरिया, डीएपी और अन्य जटिल उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में उल्लेखनीय कमी नहीं आती या फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (पीऐंडके) उर्वरकों के घरेलू उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल सल्फर, अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड की कीमतें नहीं घटतीं, तो वित्त वर्ष 2027 के लिए उर्वरक सब्सिडी बजट अनुमान से अधिक जा सकती है।

खाड़ी क्षेत्र भारत की यूरिया जरूरत का 20 से 30 फीसदी और डीएपी आयात का 30 फीसदी हिस्सा पूरा करता है। साथ ही, भारत के एलएनजी आयात का लगभग 50 फीसदी भी इसी क्षेत्र से आता है, जो यूरिया उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चे माल के रूप में काम आता है। उच्च सब्सिडी का यह भी मतलब है कि देश में दूसरे सबसे अधिक उपभोग वाले उर्वरक डीएपी की कीमत 1,350 रुपये प्रति बोरी (50 किलो) पर स्थिर रखी जाएगी और अतिरिक्त लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। वित्त वर्ष 2027 में केंद्र ने कुल 1,70,781 करोड़ रुपये के उर्वरक सब्सिडी प्रावधान में से 54,000 करोड़ रुपये गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए निर्धारित किए थे, जो वित्त वर्ष 2026 के संशोधित अनुमान 60,000 करोड़ रुपये से लगभग 10 फीसदी कम था। बुधवार के फैसले के बाद नाइट्रोजन पर प्रति किलो सब्सिडी पिछले खरीफ के मुकाबले 10 फीसदी बढ़ी है, जबकि फॉस्फोरस पर 21 फीसदी और सल्फर पर 21.07 फीसदी की वृद्धि की गई है। पोटाश पर सब्सिडी पिछले वर्ष के स्तर 2.38 रुपये प्रति किलो पर यथावत रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये दरें 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक लागू करने का निर्णय लिया गया। एनबीएस योजना के तहत पीएंडके उर्वरकों की 28 ग्रेड पर यह सब्सिडी लागू होती है। यह योजना अप्रैल 2010 से लागू है। वैश्विक स्तर पर पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद यूरिया की कीमतें संकट पूर्व स्तर से 200–250 डॉलर बढ़कर लगभग 700 डॉलर प्रति टन पहुंच गई हैं। वहीं डीएपी की कीमतें 650–670 टन से बढ़कर 750–770 डॉलर प्रति टन हो गई हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने लगभग 56.5 लाख टन यूरिया, 45.7 लाख टन डीएपी और 25.4 लाख टन अमोनिया का आयात किया। डीएपी, एमओपी और एनपीके जैसे गैर-यूरिया उर्वरकों की खुदरा कीमतें विनियंत्रित हैं और इन्हें निर्माता तय करते हैं, जबकि केंद्र सरकार हर वर्ष निश्चित सब्सिडी देती है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (इक्रियर) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत चीन के बाद उर्वरक उत्पादन और खपत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 707 लाख टन उर्वरकों का उपभोग किया, जो लगभग 330 लाख टन पोषक तत्वों के बराबर है। हालांकि मजबूत घरेलू उद्योग के बावजूद भारत का उर्वरक क्षेत्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भर है। यूरिया उत्पादन में उपयोग होने वाली प्राकृतिक गैस का लगभग 85 फीसदी आयातित है, जबकि फॉस्फेटिक रॉक फॉस्फेट का 90 से 95 फीसदी और फॉस्फोरिक एसिड का आधा हिस्सा विदेश से आता है।

जयपुर मेट्रो के लिए 13,000 करोड़ रुपये

सुधीर पाल सिंह
नई दिल्ली, 8 अप्रैल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना को मंजूरी दे दी। 41 किलो मीटर लंबा यह उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक जाएगा, जिसमें 36 स्टेशन होंगे। परियोजना की कुल लागत 13,037.66 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस परियोजना को राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड लागू करेगी, जो केंद्र और राज्य सरकार का 50:50 संयुक्त उपक्रम है। फेज-2 कॉरिडोर से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, वीकेआईए, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल व स्टेडियम, अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर जैसे प्रमुख गतिविधि केंद्रों को कनेक्टिविटी मिलेगी। एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे। यह कॉरिडोर इंटरचेंज और फीडर सिस्टम के माध्यम से मौजूदा फेज-1 से जुड़ा रहेगा। बयान में कहा गया कि परियोजना की आर्थिक आंतरिक प्रतिफल दर (ईआईआरआर) 14 प्रतिशत से अधिक है, जो इसकी मजबूत सामाजिक-आर्थिक व्यवहार्यता को दर्शाती है।

राजस्थान रिफाइनरी में निवेश को मंजूरी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना की लागत को 43,129 करोड़ से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये करने और एचपीसीएल द्वारा 8,962 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी। इस वृद्धि के बाद एचपीसीएल का कुल इक्विटी निवेश 19,600 करोड़ रुपये हो जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश के लिए जलविद्युत परियोजना

सीसीईए ने अरुणाचल प्रदेश में दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं (एचईपी) स्थापित करने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। इसमें अंजाव जिले में लोहित नदी पर स्थित कलाई-2 एचईपी के निर्माण के लिए लगभग 14,105.83 करोड़ रुपये तथा कामले, क्रा दादी और कुरुंग कुमे जिलों में कमला एचईपी के निर्माण के लिए लगभग 26,069.50 करोड़ रुपये शामिल हैं।

असम चुनाव: करोड़पति उम्मीदवार बढ़े

अदिति बगड़िया
नई दिल्ली, 8 अप्रैल

इस साल असम विधान सभा चुनावों में मैदान में उतरे हर सात में से एक उम्मीदवार पर आपराधिक मामले हैं, जो पिछले चुनाव की तुलना में मामूली गिरावट को दर्शाता है। हालांकि इस बार करोड़पति उम्मीदवारों की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के विश्लेषण के अनुसार 722 उम्मीदवारों में से 102 उम्मीदवारों (14 फीसदी) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि 2021 में 15 फीसदी उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले थे। 82 उम्मीदवारों (11 फीसदी) पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं जो पांच साल पहले 12 फीसदी से कम है।

असम के कुल 126 निर्वाचन क्षेत्रों में से 8 ही अति संवेदनशील यानी 'रेड अलर्ट' वाली सीटें हैं जिनमें तीन या अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं।

हालांकि उम्मीदवारों के बीच संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। करोड़पति उम्मीदवारों का अनुपात 2021 में 28 फीसदी था जो इस बार बढ़कर 39 फीसदी हो गया है। औसत संपत्ति भी बढ़कर लगभग 3.25 करोड़ रुपये हो गई है जो पिछले चुनाव के 2.10 करोड़ रुपये औसत संपत्ति से अधिक है। सभी उम्मीदवारों की कुल घोषित संपत्ति लगभग 2,352 करोड़ रुपये है, जो चुनावों में धनबल की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। उम्मीदवारों की जनसांख्यिकी एक परिचित रूझान दिखाती है। अधिकतर उम्मीदवार (60 फीसदी) 41 से 60 वर्ष की आयु के बीच हैं।

केरल: माकपा और कांग्रेस के लिए 'आर या पार' जैसी स्थिति

सुंदर सेतुरामन
नई दिल्ली, 8 अप्रैल

केरल में 9 अप्रैल को होने वाले विधान सभा चुनाव सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए 'आर या पार' जैसी स्थिति है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए यह एक तरह की कसौटी है कि क्या पार्टी पिछले लोक सभा और हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों से मिली जीत को आगे बढ़ा सकती है और विधान सभा में अपना खाता फिर से खोलकर केरल की राजनीति में तीसरे ध्रुव के रूप में उभर सकती है।

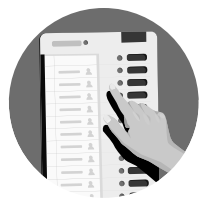

विधान सभा चुनाव 2026

माकपा के लिए देश में अपने अंतिम गढ़ को बचाने के लिए जीत बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सत्ता से बेदखल होने के बावजूद केरल में माकपा की प्रासंगिकता बनी हुई है। उसके नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) ने पिछले चार विधान सभा चुनावों में से तीन में जीत हासिल की है। यहां तक कि 2011 में, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) से उसे हार मिली थी, तब भी हार का अंतर बहुत कम था। हालांकि, राज्य की जनता लोक सभा चुनावों में कांग्रेस का समर्थन करना पसंद करती है। स्थानीय निकाय चुनावों में हालिया हार के बावजूद पार्टी सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है।

माकपा के महासचिव एमए बेबी ने कहा, 'हमें पूरा भरोसा है। अगर हम अपने अच्छे कामों का संदेश हर घर और हर मतदाता तक पहुंचा सकें, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे। पिछले दस वर्षों में घोर गरीबी का उन्मूलन एक बड़ी उपलब्धि रही है। बुनियादी ढांचे के विकास में हम पहले पिछड़े हुए थे, और उसमें भी हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले दस वर्षों में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।

केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सांप्रदायिक तनाव नहीं है, और विभिन्न धर्मों के लोग पूर्ण सद्भाव से रहते हैं। इसमें भी एलडीएफ प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई है।'

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
रिश्तों की जमापूँजी
प्रधान कार्यालय: स्टार हाऊस, सी - 5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: 022 6668 4414/15.
HeadOffice.Security@bankofindia.bank.in

प्रस्ताव का अनुरोध

बैंक ऑफ इंडिया, सिस्टम इंटीग्रेटर से सुरक्षा गैजेट्स जैसे – फायर अलार्म, सुरक्षा अलार्म, सीसीटीवी सिस्टम इत्यादि के संस्थापन हेतु तीन वर्षों के एमपैनेलमेंट के लिए "प्रस्ताव आमंत्रित" करता है।

प्रस्ताव प्रस्तुति की अंतिम तिथि **08–05–2026 अपराहन 01.00 बजे** तक है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण हमारे वेबसाइट **https://bankofindia.bank.in** पर उपलब्ध है।

(डीजीएम एवं सीएसओ) सुरक्षा विभाग

विचार

आइए, हम मिलकर भारत की नारी शक्ति को सशक्त करें

नरेंद्र मोदी

21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है, जब समानता, समावेशन और जनभागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी। यह ऐसा समय है, जब हमारे देश की संसद को एक महत्त्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है, जो हमारे लोकतंत्र को अधिक व्यापक एवं और अधिक प्रतिनिधिक बनाए। संसद का यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोक सभा और विधान सभा आदि संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा।

यह क्षण इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है जब देश का वातावरण उत्सव, नवीनता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में भारत के अलग-अलग हिस्सों में अनेक पर्व मनाए जाएंगे। असम के लोग रोंगाली बिहू मनाने वाले हैं और ओडिशा में महा बिशुबा पणा संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी। केरलम में विषु पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सुकता से पुथांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को बैसाखी के पर्व का इंतजार है। हमारे ये पावन पर्व हर किसी में एक नई आशा का संचार करने वाले हैं। भारत के साथ-साथ दुनियाभर में इन त्योहारों को मनाने वाले सभी लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये कामना करता हूं कि ये दिव्य और पावन अवसर हम सभी के जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आएं।

इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं, जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की है। इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्त्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्त्व को कम करके आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।

हमारी नारीशक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारीशक्ति मिसाल बन रही है। साइंस ऐंड टेक्नॉलजी से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, खेल के मैदान से लेकर सशस्त्र बलों तक और संगीत से लेकर कला के क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं-बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब माताओं-बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तीकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद भी राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। इस कमी को अब दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं, तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है। इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में सुधार भी होता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है।

पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार-बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके। फिर भी, इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है। अब जरूरत है कि 2029 के लोक सभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधान सभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर हमारे संविधान की मूल भावना के साथ गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां समानता न केवल संविधान में निहित हो, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाए। विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राष्ट्र का भविष्य तय करने में प्रत्येक नागरिक की समान भूमिका हो। अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। दशकों से इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। इस पर चर्चा हुई है, इसे बार बार दोहराया गया है। अगर अब भी हम इसे आगे टालते हैं, तो उसका अर्थ यही होगा कि हम उस असंतुलन को और लंबा खींच रहे हैं, जिसे हम पहचानते भी हैं और सुधारने की क्षमता भी रखते हैं। आज भारत पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारी संस्थाएं सभी नागरिकों, विशेष रूप से हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करें। इससे न सिर्फ दशकों पुराना संकल्प पूरा होगा, बल्कि विकास की गति को बनाए रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। यह हमारे लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने और भविष्य के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह समय सामूहिक संकल्प का है। यह किसी एक सरकार, एक दल या एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का विषय है। हमें मिलकर इस कदम के महत्त्व को समझना है और मिलकर ही इसे साकार करना है। यही हमारी नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व भी है, इसलिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ फैसले अपने समय से बड़े होते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत समय के साथ खुद को और अधिक न्यायपूर्ण और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता में होती है। संसद का यह ऐतिहासिक सत्र करीब आ चुका है। मैं सभी दलों के सांसदों से हमारी नारीशक्ति के लिए इस महत्त्वपूर्ण कदम का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। हम जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस दायित्व को पूरा करें। आइए, हम अपने लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

APPOINTMENTS

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
चंदेर मुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई – 400 021,
दूरभाष: 022- 66387891,
वेब साईट: www.centralbank.bank.in

विशेषज्ञ श्रेणी में जोखिम प्रबंधन स्ट्रीम में अधिकारियों के चयन हेतु भर्ती प्रक्रिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है, जिसकी अखिल भारतीय शाखा नेटवर्क में 4500 से अधिक शाखाएं हैं, जिनका कुल व्यवसाय ₹8,12,000 करोड़ से अधिक का है, जो 33,000 से अधिक कर्मचारियों की प्रतिबद्ध टीम द्वारा संचालित है, विशेषज्ञ श्रेणी में जोखिम प्रबंधन स्ट्रीम के पदों के लिए अनुभवी/योग्य पेशेवरों की भर्ती का प्रयोजन करता है. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे बैंक की वेबसाइट https://www.centralbank.bank.in देखें.

मुंबई
दिनांक: **09.04.2026**
मुख्य महाप्रबंधक (मासंप्र)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) निम्नलिखित के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित करता है :

सरकारी ई-मार्केट पोर्टल-250 ऑल-इन-वन पीसी की आपूर्ति, सुस्थापित एवं रखरखाव

बोली सं: - जीईएम/2026/बी/7405670 दिनांक 06.04.2026

उपर्युक्त निविदा के लिए दस्तावेज उल्लिखित वेबसाइटों पर **www.iob.bank.in** एवं **www.gem.gov.in** उपलब्ध है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा का विवरण और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के लिए, उक्त वेबसाइट **www.gem.gov.in** का संदर्भ लेते रहें।

बैंक ऑफ़ इंडिया
आंचलिक कार्यालय : भोपाल अंचल
बैंक ऑफ इंडिया भवन जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन: 0755-2556770, 2555169, ई-मेल: bhopal.assetrecovery@bankofindia.co.in

चल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

ऋणी व जमानतदारोंको विशेष रूप से व सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित सुरक्षित ऋण प्रदाता बैंक द्वारा बंधक / प्रभारित चल सम्पत्ति का बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया है। बन्धक सम्म की बिक्री "**जो है, जहाँ है, जैसी है एवं जैसी भी स्थिति में है, दायित्व रहित**" के आधार पर की जायेगी ।

ऋणी का नाम	पंजीयन क्रमांक / मेक / मॉडल	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि
भोपाल रिकवरी शाखा, भोपाल, फोन : 8975728625, 9752153767, 7355725919 Account to deposit auction sale proceeds- 902990200000033, IFSC- BKID0009029		
मेसर्स रीति गर्ग ट्रेड लिंक (प्रोपराइटर- श्रीमती रीति गर्ग) पता- डी-1, फेस-2, गार्डन होम्स, अलकापुरी, सिटी सेन्टर, ग्वालियर- 474011 बकाया राशि 3,91,56,328/- +दिनांक 23.06.2025 से देय ब्याज एवं अन्य खर्च	MP07ZJ9393 (Model: 2023) Regn. Date: 20-11-23 Ashok Leyland Ltd & NE5525N/39 TT CC Chasis No. MB1U1VLD7PPKW3347 Engine No. PKPZ503358	₹ 19,35,000/- ₹ 1,93,500/-
	MP07ZJ5700 (Model: 2023) Regn. Date: 20-11-23 Ashok Leyland Ltd & NE5525N/39 TT CC Chasis No. MB1U1VLD9PPKW5682 Engine No. PKPZ503939	₹ 19,35,000/- ₹ 1,93,500/-
	MP07ZK9044 (Model: 2023) Regn. Date: 19-12-23 Ashok Leyland Ltd & NE5525N/39 TT CC Chasis No. MB1U1VLD2PPDY4063 Engine No. PDPZ508961	₹ 16,12,000/- ₹ 1,61,200/-
	MP07ZJ9097 (Model: 2023) Regn. Date: 19-12-23 Ashok Leyland Ltd & NE5525N/39 TTCC Chasis No. MB1U1VLD2PPDY3950 Engine No. PDPZ508994	₹ 16,12,000/- ₹ 1,61,200/-
	MP07ZK9986 (Model: 2023) Regn. Date: 26-12-23 Ashok Leyland Ltd & NE5525N/39 TTCC Chasis No. MB1U1VLD7PPDY3944 Engine No. PDPZ508979	₹ 16,12,000/- ₹ 1,61,200/-
	MP07ZK9944 (Model: 2023) Regn. Date: 26-12-23 Ashok Leyland Ltd & NE5525N/39 TTCC Chasis No. MB1U1VLD5PPEY2908 Engine No. PEPZ508674	₹ 19,35,000/- ₹ 1,93,500/-
	MP07ZJ9029 (Model: 2023) Regn. Date: 19-12-23 Ashok Leyland Ltd & NE5525N/39 TTCC Chasis No. MB1U1VLD6PPDY3949 Engine No. PDPZ508886	₹ 16,12,000/- ₹ 1,61,200/-
	कुल आरक्षित मूल्य ₹ 122.53 लाख, कुल धरोहर राशि ₹ 12,25,300/-	
श्री विक्रांत सिंह पता- म.नं. 160/2, वार्ड नं. 12, न्यू ज्वालामुखी कालोनी, उमरिया, म.प्र. 484661 कार्यालय का पताः सॉलिश ट्रेक्टर, शहडोल रोड, छापा कलेरी के पास, उमरिया म.प्र.-484661 मांग सूचना दिनांक 03.05.2025 के अनुसार बकाया राशि- ₹ 4,70,22,699.38 +दिनांक 30.04.2025 से देय ब्याज एवं अन्य खर्च	MP54-ZB1114, Tata Motors/Tata Signa BS6 Trip Trailer HP 300.16/WB-3320 Chasis No. MAT828048PAN15238 Engine No. 32L95442496 (Model: 2024)	₹ 34,20,000/- ₹ 3,42,000/-
	CG10-BW0188, Tata Motors/Tata Signa BS6 Trip Trailer HP 300.16/WB-3320 Chasis No. MAT828048RAH12649 Engine No. 42H95477446 (Model: 2024)	₹ 35,10,000/- ₹ 3,51,000/-
	CG10-BW0189, Tata Motors/Tata Signa BS6 Trip Trailer HP 300.16/WB-3320 Chasis No. MAT828048RAH12356 Engine No. 42G64400343 (Model: 2024)	₹ 35,10,000/- ₹ 3,51,000/-
	कुल आरक्षित मूल्य ₹ 104.40 लाख, कुल धरोहर राशि ₹ 10,44,000/-	

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 28.04.2026, सुबह 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

ई-नीलामी की शर्तें :-
(1) ई-नीलामी /बिडिंग "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बिडिंग" के माध्यम से "जैसा है जहां है, जो है जैसा है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर वेबसाइट **http://BAANKNET.com** पर की जावेगी। इच्छुक निविदाकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व वेबसाइट में नियम एवं शर्तों की जानकारी प्राप्त करें।
(2) वाहन का निरीक्षण दिनांक **27.04.2026** को या उससे पहले सुबह 10 से सायं 5 बजे तक शाखा प्रबंधक /प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।
(3) बिक्री की पुष्टि होने होने पर सफल खरीदार को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत (जिसमे ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम शामिल हैं) तुरंत जमा करानी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिन के अंदर ऊपर दिये गए शाखा के अकाउंट नंबर मे जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा मे राशि जमा न करने की स्थिति मे बोलिकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जायगी।
(4) बोली निर्धारित आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर शुरू होगी। बोली वृद्धि राशि रु. **10000/-** रहेगी।
(5) सफल खरीददार को वाहन पर भुगतान की जाने वाली सांविधिक देयताएं/ असांविधिक देयताएं/ स्टाम्प ड्यूटी / अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/ ट्रांसफर शुल्क / सभी शुल्क / असेसमेंट चार्जेस / अन्य प्रभार जिसमें पंजीयन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, कर, लागू टीडीएस इत्यादि व्ययों का भुगतान करना होगा।
(6) प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी या सभी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने / निरस्त अथवा ई-नीलामी की नियम एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
(7) अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त वर्णित दूरभाष क्र. पर संबंधित शाखा प्रबंधक से संपर्क करें: अथवा अंचल कार्यालय, भोपाल फोन : 0755-2556770 / 2555169 से संपर्क करें।

स्थान : भोपाल, दिनांक : 08.04.2026 प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : छठा तल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के बगल में, निकट अशोक वाटिका, बीआरटीएस, इस्कॉन – आंबली रोड, बोडकादेव, आंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054
कार्पोरेट कार्यालय : सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कम्पाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ईस्ट), मुंबई – 400063, महाराष्ट्र, भारत,
फोन नं. : +91 22 61796400 **ई–मेल :** contact@kifshousing.com **वेबसाइट :** www.kifshousing.com
सीआईएन : U65922GJ2015PLC085079 **आरबीआई सीओआर :** डीओआर–00145

भौतिक कब्जा सूचना

1. **दिलीप भाबर (आवेदक)**
2. **मुन्नी भाबर (सह–आवेदक)**
3. **श्रवण खरादी (सह–आवेदक)**

सम्पत्ति पता : मकान नंबर 123/3, पीएच. नंबर 46, वार्ड नंबर 07, ग्राम कालडेला, तहसील थांडला, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश–457777.

जबकि
अधोहस्ताक्षरी ने, केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **19–12–2024** जारी की थी, जिसमें आपसे आपके **ऋण खाता संख्या LNHLJHA007602 और LNHERTM014241 के तहत सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रू. 7,69,356/– (रुपए सात लाख उनहत्तर हजार तीन सौ छप्पन मात्र) और रू. 5,54,345/– (रुपए पांच लाख चौवन हजार तीन सौ पैंतालीस मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।
आप, राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः आपको और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक रखी गई नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प